



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126406

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17822 वर्ष 2026

शिव प्रसादआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार, सुनीता चौहान

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय संजीव कुमार, न्यायमूर्ति

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुनीता चौहान और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से पुलिस थाना- बरदह, जिला- आजमगढ़ में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या)/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 219 वर्ष 2021, भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 412 और 413 के तहत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है और उसके बाद, एक फर्जी मुठभेड़ में पुलिस ने आवेदक को गिरफ्तार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कथित बरामदगी का कोई सार्वजनिक गवाह नहीं है और कोई शिनाख्त कार्यवाही नहीं की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि कथित बरामद संपत्ति वर्तमान मामले से संबंधित है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अपीलकर्ता ने अपना आपराधिक इतिहास स्पष्ट कर दिया है और वह अन्य मामलों में जमानत पर है और इस मामले के बाद गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवेदक/अपीलकर्ता 31.12.2021 से जेल में बंद है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी, अर्थात्, धर्मेन्द्र बनवासी और सोनू बनवासी को इस न्यायालय की समान अधिकारिता वाली पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 16091 वर्ष 2022 और आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 27448 वर्ष 2022 में पारित आदेशों दिनांक 16.05.2022 और 14.07.2022 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. तर्कों के दौरान, आवेदक की विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष सह-आरोपी, अर्थात्, धर्मेन्द्र बनवासी और सोनू बनवासी के जमानत आदेश की एक छायाप्रति (फोटोकॉपी) प्रस्तुत की, जिसे पत्रावली पर लिया जाता है।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक एक हिस्ट्रीशीटर (आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति) है, लेकिन निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि समान स्थिति वाले सह-आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
6. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और पत्रावली के साथ-साथ सह-आरोपी के आदेश का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। समानता के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक-शिव प्रसाद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसका वह आरोपी है, या जिसके घटित होने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनबद्ध पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प खुला रहेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (तदनुरूप बीएनएस की धारा 269) के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (तदनुरूप बीएनएस की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (तदनुरूप बीएनएस की धारा 209) के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले के खुलने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (तदनुरूप बीएनएस की धारा 351) के तहत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

जून 9, 2026

आदित्यजी

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"